



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 302]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 6, 2010/अग्रहायण 15, 1932

No. 302]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 6, 2010/AGRAHAYANA 15, 1932

बाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(बाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क प्रबंधनेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2010

(निर्णायक समीक्षा)

विषय : चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित 20-100 ग्राम भार प्रति मीटर के सिल्क फैब्रिक के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत।

फा. सं. 15/24/2010-डीजीएडी.—वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और वसूली और क्षति-निर्धारण) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) ने चीन जन गण (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल से अथवा वहाँ से निर्यातित सिल्क फैब्रिक के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम का दिनांक 15 नवम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. 14/20/2004-डीजीएडी द्वारा प्रकाशित किया गया था। जांच परिणाम के आधार पर संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुओं पर राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 26-12-2006, की अधिसूचना सं. 121/2006-सीमाशुल्क के अनुसार पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

2. निर्णायक समीक्षा का शुरुआत

यतः सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 की धारा 9क (5) के अनुसार यदि लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को समाप्त नहीं किया जाता तो वह शुल्क लागू किए जाने की तारीख से पांच वर्ष

की अवधि के पश्चात् समाप्त हो जाएगा और प्राधिकारी द्वारा इस बात की समीक्षा की जानी अपेक्षित है कि क्या शुल्क समाप्त होने से पाटन एवं क्षति की पुनरावृति होने की संभावना है। इस संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2006 की डब्ल्यू पी संख्या 16893 में यह निर्णय दिया है कि निर्णायक समीक्षा अनिवार्य है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों के अनुसरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी यह जांच करने के लिए कि क्या शुल्क समाप्त किए जाने से पाटन एवं क्षति जारी रहेगी अथवा उससे उसकी पुनरावृति की संभावना बनी रहेगी पाटनरोधी शुल्क के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार एतद्वारा निर्णायक समीक्षा की शुरुआत करते हैं।

3. विचाराधीन उत्पाद

वित्तमान जांच में शामिल उत्पादक केवल पावर लूम द्वारा उत्पादित 20-100 ग्राम भार प्रति मीटर का सिल्क फैब्रिक है (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा जाएगा)। जैसाकि दिनांक 15 नवम्बर, 2006 के अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/20/2004-डीजीएडी में इंगित किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद में केवल विद्युत करघा से उत्पादित सिल्क फैब्रिक शामिल है न कि हथकरधा से उत्पादित सिल्क फैब्रिक। सिल्क फैब्रिक आधारभूत कच्ची सामग्री-कच्चे रेशम से उत्पादित किया जाता है जिसे रेशम के कृमिकोष से प्राप्त किया जाता है। संबद्ध वस्तु को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के शीर्ष 5007 के तहत वर्गीकृत किया गया है और सामान्यतः इसे उप-शीर्ष 5007 9000 के तहत शामिल किया जाता है। संबद्ध वस्तुओं को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के उपर्युक्त 5007 1000, 5007 2000, 5007 2010 तथा 5007 2090 के तहत शामिल किए जाने की अनुमति दी गई है। तथापि यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और संबद्ध जांच पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

4. प्रक्रिया

(I) इस जांच से यह निर्धारित होगा कि क्या शुल्क समाप्त करने से पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृति होने

की संभावना है। प्राधिकारी इस बात की जांच करेंगे कि क्या पाटन को रोकने के लिए शुल्क को लागू रखना आवश्यक है और क्या शुल्क को समाप्त करने या उसमें परिवर्तन करने, अथवा दोनों होने की स्थिति में क्या क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है:-

- (i) समीक्षा में दिनांक 15 नवम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. 14/20/2004-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल होंगे। इस समीक्षा जांच में शामिल देश चीन जन. गण. है।
- (ii) वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पी ओ आई) 1 अप्रैल, 2009 से 30 जून, 2010 (15 महीने) होगी। तथापि क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 2006 से मार्च, 2007, अप्रैल, 2007 से मार्च 2008 तथा अप्रैल, 2008 से मार्च, 2009 तथा प्रस्तावित जांच अवधि शामिल होगी।
- (iii) उपर्युक्त नियमों के नियम 6,7,8,9, 10,11,16,17,18,19 तथा 20 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों के पश्चात् इस समीक्षा पर लागू होंगे।

(II) सूचना प्रस्तुत करना :

घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित प्रपत्र (घरेलू उद्योग हेतु आवेदन) में सूचना प्रस्तुत करना और शुल्क जारी रखने की आवश्यकता के प्रमाणों का उल्लेख करते हुए पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने अथवा दोनों होने की संभावना के विषय में इस अधिसूचना के जारी किए जाने के चालीस (40) दिनों के भीतर सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

संबद्ध देश में निर्यातक, भारत में स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से उनकी सरकारें, भारत में ऐजूर संबद्ध ज्ञात आयातकों एवं प्रयोक्ताओं को निर्धारित ढंग एवं पद्धति में संगत सूचना प्रस्तुत करने और प्राधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :—

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

कमरा सं. 243

उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित ढंग एवं पद्धति में इस जांच से संगत निवेदन प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय निवेदन प्रस्तुत करने वाली किसी पार्टी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए उस गोपनीय निवेदन का एक अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा।

(III) समय सीमा :

घरेलू उद्योग से सूचना प्राप्त होने पर सभी हितबद्ध पक्षकारों जिनके पते उपलब्ध होंगे, को एक पत्र द्वारा लिखित में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की सलाह दी जाएगी ताकि वह ऐसा पत्र

जारी करने की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित पते पर प्राधिकारी के पास पहुंच जाए। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार, जिनका पता उपलब्ध नहीं है, भी घरेलू उद्योग के आवेदन की तारीख से 40 दिनों के भीतर टिप्पणियां/सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रयोजनार्थ आवेदन का अगोपनीय रूपांतर सार्वजनिक फाइल में रखा जाएगा। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

(IV) सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण :

नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय सारांश वाली उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है। यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं करता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

पी. के. चौधरी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

**(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND
ALLIED DUTIES)**

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2010

(Sunset Review)

Subject : Initiation of Sunset review of Anti-dumping duty imposed on imports of Silk Fabric of weight 20-100 gms per meter originating in or exported from China PR.

F. No.15/24/2010-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) recommended imposition of Anti Dumping Duty on imports of Silk Fabric originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as subject country). The final findings notification of the Authority was published vide notification No. 14/20/2004-DGAD dated 15th November, 2006. On the basis of the findings, anti-dumping duties on the subject goods imported from the subject country were imposed by the Department of Revenue vide notifications No. 121/2006-Customs dated 26-12-2006.

2. Initiation of Sunset Review

Whereas in terms of Section 9A(5) of the Customs Tariff (Amendment) Act 1995 the anti-dumping duties imposed, shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition

and the Authority is required to review, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In this regard, Hon'ble Delhi High Court in WP No 16893 of 2006 held that sunset review is mandatory. Therefore, pursuant to the above orders of the Hon'ble High Court, the Designated Authority hereby initiates sunset review in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of Antidumping Rules to examine whether cessation of the duty would lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

3. Product under Consideration

The product involved in the present investigation is Silk Fabric of weight 20 -100 gms per meter produced in the power looms only (hereinafter also referred to as subject goods). As was indicated in the Final Finding vide Notification No.14/20/2004-DGAD dated 15th November, 2006, only silk fabrics produced by power looms are covered in the product under consideration and not the fabrics produced in the handloom sector. Silk fabric is produced from the basic raw material—raw silk, which is drawn from silk cocoons. The subject good is classified under Heading 5007 of the Customs Tariff Act and generally gets covered under Sub-heading 5007 9000. The subject goods are cleared under Sub-headings 5007 1000, 5007 2000, 5007 2010 and 5007 2090 of the Customs Tariff Act. However, the customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the subject investigation.

4. Procedure

(I) The investigation will determine whether the expiry of the measure would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. The Authority will examine whether the continued imposition of the duties is necessary to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both :—

- (i) The review will cover all aspects of Notification 14/20/2004-DGAD dated 15th November, 2006. The country involved in this review investigation is China PR.
- (ii) The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is from 1st April, 2009 to 30th June, 2010 (15 months). The injury investigation period will however cover the periods, April 2006 to March 2007, April 2007 to March 2008 and April 2008 to March 2009 and the proposed POI.
- (iii) The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

(II) Submission of Information :

The Domestic industry is required to submit information on prescribed pro forma (Application for Domestic industry) and information on likelihood of continuance or recurrence of dumping and injury or both substantiating the need for continuation of duty within forty days (40 days) of issue of this notification.

The exporters in subject country, their government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned would be addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority in the following address :

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
Room No. 243

Udyog Bhavan New Delhi-110011

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

(III) Time Limit :

On receipt of information from domestic industry, all interested parties, whose addresses are available, would be advised through a letter to offer their comments in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of issuance of such letter. Any other interested party, whose address is not available, may also submit comments/information within 40 days from the date of application from Domestic industry. For this purpose non confidential version of the application would be placed in the public file. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

(IV) Inspection of Public File:

In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

P. K. CHAUDHERY, Designated Authority